'कांग्रेस कमीशन देखती थी, हम ''सबका विकास'' में विश्वास रखते हैं'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष संवाद में विकसित राजस्थान की रूपरेखा पर चर्चा की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर-सिरोही, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा के जनप्रतिनिधियों और जिला अध्यक्षों से संवाद किया।

- **मुख्यमंत्री ने कहा, कि शेखावाटी की हवेलियां हमारी विरासत हैं। यदि हम इनका संरक्षण व संवर्धन कर टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से विकास करें तो पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा व स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।**

जयपुर, 26 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर-सिरोही, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और भाजपा जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश के विकास पर संवाद किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान2047 की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि जन आकांक्षाएं राज्य सरकार के विजन का केन्द्र बिन्दु हैं। हमारी सरकार ने बजट में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बिना किसी भेदभाव के बजट का प्रावधान किया है। हमारी सरकार सबका साथ-सबका विकास में विश्वास रखती है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार कमीशन के लिए काम करती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां हमारी विरासत हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि विरासत और विकास दोनों साथ चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में घरेलू पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यदि हम इन हवेलियों का संरक्षण और संवर्धन कर टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से इनका विकास करें तो इससे पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा।

शर्मा ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक किसानों को केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं से लाभान्वित करें।

इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) को धरातल पर शुरू किया। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दिया है।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान वे पूरी तैयारी कर सदन में होने वाली चर्चा में भाग लें।

एससीओ समिट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महत्वपूर्ण रक्षा मुद्दों को संबोधित करने में एससीओ विफल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस मंच पर भी झलकता है। जून में हुए एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने हिंदू पर्यटकों पर हमले का जिक्र न होने पर आपत्ति जताई, जिससे संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। भारत ने ईरान पर इज़रायली हमले की निंदा करने वाले एससीओ बयान में भी शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालाँकि भारत-चीन संबंधों में हाल ही में आई नरमी और ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर नए टैरिफ दबाव ने इस बार शी-मोदी बैठक से सकारात्मक उम्मीदें जगा दी हैं। एरिक ओलेंडर के अनुसार, ''संभव है कि भारत अपनी प्रतिष्ठा को थोड़ा पीछे रखकर इस साल के एससीओ विवादों को भुला दे, क्योंकि चीन के साथ संबंध सुधारना मोदी की वर्तमान प्राथमिकता है।'' ट्रंप के रुख से आहत मोदी जान गए है कि भारत के पास कूटनीतिक दांव के विकल्प सीमित है। इसलिए मोदी सरकार ने विदेश नीति के अन्य विकल्प तलाशने का निर्णय किया है चीन से हाथ मिलाना इसी का अंग है। बीजिंग भारत की दुविधा को समझता है और उसकी गणना में भारत के अमेरिका के पाले में जाने से अच्छा है स्वतंत्र व तटस्थ भार उसके पास आ जाए। विश्लेषकों को उम्मीद है कि भारत और चीन सीमा से सेना हटाने, व्यापार और वीज़ा नियमों में ढील, जलवायु सहयोग, और जन-संपर्क को बढ़ाने जैसे कई छोटे कदमों की घोषणा कर सकते हैं। हालाँकि इस सम्मेलन से बड़े नीति निर्णयों की उम्मीद नहीं है, फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके प्रतीकात्मक महत्व को कम करके नहीं आँकना चाहिए। ओलेंडर के शब्दों में, यह शिखर सम्मेलन प्रतीकों के बारे में है और बहुत शक्तिशाली प्रतीकों के बारे में। सम्मेलन के बाद मोदी चीन से रवाना हो जाएंगे, जबकि पुतिन बीजिंग में होने वाली द्वितीय विश्व युद्ध की सैन्य परेड में भाग लेने के लिए सप्ताहभर चीन में रहेंगे - जो रूस के बाहर उनका एक असाधारण रुप से लंबा दौरा होगा।

हैल्थ इंश्योरैंस और...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर जीएसटी को शून्य कर दिया जाए। अब यह रिपोर्ट परिषद के पास है, जहाँ अंतिम निर्णय राज्य के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार के हाथ में होगा। कुछ वैकल्पिक सुझाव भी विचाराधीन हैं - जैसे जीएसटी को आंशिक रूप से घटाकर 5 प्रतिशत या 12 प्रतिशत करना, या वरिष्ठ नागरिकों अथवा 5 लाख तक की पॉलिसियों के लिए राहत देना। ये आधे-अधूरे उपाय सरकार को राजस्व में अधिक नुकसान से तो बचा लेंगे, लेकिन बीमा को वास्तव में सुलभ बनाने के उद्देश्य को कमजोर कर सकते हैं।

राज्यों की अपनी चिंताएँ जायज़ हैं। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से हर साल 2,600 करोड़ से 9,700 करोड़ तक का राजस्व आता है, जो छूट के दायरे पर निर्भर करता है। ऐसे समय में जबकि, कई राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, इस राजस्व को छोड़ना आसान नहीं होगा। बीमा कंपनियाँ भी चिंतित हैं। अगर जीएसटी हटा दिया गया, तो उन्हें अपनी सेवाओं पर मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इन मुद्दों पर परिषद में तीखी बहस की संभावना है। फिर भी, छूट के पक्ष में दलील बहुत मजबूत है। भारत लंबे समय से बीमा की कम पहुँच और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। इसका मतलब है कि बीमारी के समय या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार अपनी बचत पर निर्भर रहते हैं। जीएसटी को हटाकर सरकार की तरफ से यह संकेत जाएगा कि वह बीमा के जरिए लोगों को जोखिम बांटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। जिससे परिवारों की वित्तीय असुरक्षा कम होगी। यह वित्तीय समावेशन (फायनैंशियल इन्क्लूज़न) और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यापक नीति के अनुरूप भी है।

इस निर्णय का समय भी बहुत अहम है। जीएसटी परिषद की सितंबर बैठक में टैक्स स्लैब्स को बदलकर उन्हें आसान बनाने की संभावना है। इसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब हटाकर सिर्फ दो दरें, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव है। इस व्यापक सुधार के बीच बीमा पर छूट सबसे ज्यादा उपभोक्ता-हितैषी कदम के रूप में उभर सकती है। सरकार इसे दिवाली तोहफे के रूप में पेश कर सकती है, और इसे अक्टूबर में त्योहारी सीज़न से पहले लागू किया जा सकता है। इससे बीमा कंपनियों को अपने उत्पादों की कीमतें फिर से तय करने और बाज़ार में उन्हें अधिक आकर्षक बनाने का मौका मिलेगा।

अंततः यह मुद्दा इस पर निर्भर करता है कि परिषद वित्तीय विवेक और सामाजिक ज़रूरत के बीच संतुलन कैसे बनाती है। भारत की बचत प्रणाली पहले ही बदल रही है, लोग अब सोना और अचल संपत्ति के बजाय वित्तीय साधनों में निवेश कर रहे हैं।

सुरक्षा (प्रोटैकशन) की लागत को कम करना इस प्रवृत्ति को और मज़बूत करेगा। यह एक ऐसा समाज बनाने में मदद करेगा जो ज्यादा स्वस्थ और आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, जहां बीमारी या अकाल मृत्यु से लोग कम प्रभावित हों।

अगर परिषद यह साहसिक निर्णय लेती है और पूर्ण छूट देती है, तो यह सुधार जीएसटी के लागू होने के बाद से उपभोक्ता हित में लिए गए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में गिना जाएगा। यह दिखाएगा कि टैक्स सिस्टम केवल राजस्व जुटाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति को सक्षम बनाने के लिए भी है।

आप नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी का छापा

नयी दिल्ली, 26 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 24 अस्पतालों के निर्माण से जुड़े 5,590 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर सहित 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ईडी सूत्रों ने कहा कि फिलहाल तेरह स्थानों पर तलाशी चल रही है।

धन शोधन निवारण (पीएमएलए) मामला 2018-19 में हुए कथित दिल्ली अस्पताल निर्माण से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि निर्माण में देरी होने के कारण अस्पतालों की लागत बढ़ गई। 2018-19 में आप सरकार ने अस्पतालों के निर्माण को मंज़ूरी प्रदान की थी, हालांकि परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

राहुल की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुईं प्रियंका गांधी

पटना, 26 अगस्त। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा में अपने भाई राहुल गांधी के साथ शामिल हुईं। यात्रा के दसवें दिन सुपौल जिले में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पहली बार प्रियंका गांधी इस अभियान में शामिल हुईं और राहुल गांधी के साथ खुले वाहन में लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान माहौल उत्साहपूर्ण रहा और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति देखी गई।

उपराष्ट्रपति के चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है उन्हें खुद भी कल्पना नहीं थी। तेलुगु नेता की व्यक्तिगत साख पर किसी भी प्रकार की चोट जल्द ही पूरे समुदाय के अपमान का रूप ले सकती है। इतिहास गवाह है कि ऐसी भावनाएं कभी-कभी राजनीति को हिला कर रख देती हैं।

जैसे-जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव की घड़ी नज़दीक और इसे तेलुगु अस्मिता पर प्रहार माना जा सकता है। एक आम चुनाव तेलुगु अस्मिता बनाम गठबंधन अनुशासन का रंग लेने लगा है। यदि तेलुगु देशम एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी रहती है या फिर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराती है-दोनों ही स्थितियाँ आने वाले दिनों में न केवल चुनाव परिणाम, बल्कि आंध्र तथा तेलंगाना की राजनीतिक दिशा भी तय कर सकती हैं। यह सिर्फ एक वोट नहीं, एक भावनात्मक संकेत हो सकता है।

मोदी ने ट्रंप के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तो हाल के हफ्तों में ट्रंप द्वारा चार बार फ़ोन कॉल करने के बावजूद मोदी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में उन सटीक तारीखों का ज़िक्र नहीं किया गया है जिन पर कथित तौर पर कॉल किए गए थे। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, भारतीय अधिकारियों ने इन कॉल्स पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

कौन पैदा करवा रहा है ''ट्राइबल लीडर''...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की थी और स्वयं, राजीव दत्ता, जो एक आर.पी.एस. अधिकारी हैं, नियमानुसार किसी भी मूर्ति का अनावरण नहीं कर सकते।

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इस मामले में पिछले वर्ष एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई परन्तु, राजकीय दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि एक ही वर्ष में मामले पर एफ.आर. भी लगा दी गई।

अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तथ्यों और उपलब्ध फोटो को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि इस मामले में राजनैतिक दबाव के चलते याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अदालत ने यह भी माना कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के ओ.एस.डी. राजीव दत्ता एक आर.पी.एस. अधिकारी हैं, जो सरकारी नियमानुसार किसी भी मूर्ति का अनावरण नहीं कर सकते और आरोपियों ने इसमें कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। इसलिए मुख्य सचिव इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई कर मामले का निस्तारण करें।

अमेरिका ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किए जाएंगे या गोदाम से निकाले जाएंगे।

ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत के सामान पर टैरिफ को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा की थी, जो रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया जा रहा है। अमेरिका की यह समयसीमा 27 अगस्त को खत्म हो रही है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908